साप्ताहिक हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 25 | जौनपुर, बुधवार, 11 सितम्बर 2024 | साप्ताहिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

उत्तर प्रदेश बनेगा देश का फूड बास्केट – सीएम योगी

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुरू से मंशा रही है कि उत्तर प्रदेश देश का फूड बास्केट बने। इस मंशा के पीछे उनके ठोस तर्क हैं। मसलन इंडो गेंगेटिक बेल्ट की सबसे उर्वर भूमि, अलग अलग फसलों और फलों की खेती के लिए नौ तरह की कृषि जलवायु, वर्ष पर्यन्त पानी की उपलब्धता वाली गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियां, सर्वाधिक आबादी के नाते प्रचुर मात्रा में श्रम और बाजार की उपलब्धता आदि। विभिन्न योजनाओं के जरिए योगी सरकार लगातार फसलों की उपज बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके नतीजे भी निकले हैं। पर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अलग अलग फसलों के उत्पादन पर गौर करें तो अब भी उपज बढ़ाने की बहुत संभावना है। सरकार अब इस पर ही फोकस कर रही है। यूपी एग्रीज जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के केंद्र में भी उपज बढ़ाने को मुख्य घटक माना गया है।

जिलेवार प्रमुख फसलों के अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन के गैप को पाटने का चल रहा कार्य

करीब दो साल पहले भी सरकार ने जिलेवार और फसलवार अधिकतम और न्यूनतम उत्पादकता के आंकड़े निकलवाए थे। इसका मकसद यह जानना था कि किन वजहों से किसी फसल के अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन में इतना अंतर है।इस अंतर को पाटने के लिए न्यूनतम उत्पादन वाले जिलों में संबंधित फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

यूपी एग्रीज में अब कम उत्पादन वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर फोकस

अब यही कवायद एक बार फिर योगी सरकार विश्वबैंक की मदद से यूपी एग्रीज (उत्तर प्रदेश कृषि एवम ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ी करण कार्यक्रम) के जरिए अधिक संसाधनों के साथ व्यापक इलाके में समयबद्ध और नियोजित तरीके से जा रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश करीब 24: उत्पादन के साथ कुल कृषि उत्पादन में देश में नंबर एक है। रबी की प्रमुख फसल गेंहू के मामले में यह नंबर एक तो खरीफ की प्रमुख फसल धान के उत्पादन में इसका देश में दूसरा है।

सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्यों की तुलना में यूपी

बावजूद इसके कुछ फसलों को छोड़ दें तो इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रति कुंतल राष्ट्रीय एवरेज से कम है। प्रति हेक्टेयर, प्रति कुंतल सर्वाधिक उत्पादन लेने वाले राज्यों की तुलना में तो कम है ही। वैश्विक स्तर के अधिकतम उत्पादन से तो कोई तुलना ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर चावल, गेंहू, बाजरा, ज्वार और चना को छोड़ दें तो बाकी प्रमुख फसलों में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों से पीछे है। मसलन उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता 27.59 कुंतल है तो पंजाब की उत्पादकता 43.66 कुंतल। इसी तरह यूपी में गेंहू का उत्पादन 36. 04 पंजाब में 48.62, ज्वार 15.78 आंध्र प्रदेश 30.70, बाजरा 22.21 हरियाणा 23.72, मक्का 23.31 तमिलनाडु 68.20, उर्द 4.98 महाराष्ट्र 5.68 , मूंग 3.58 महाराष्ट्र 5.55, तिल 2.26 पश्चिम बंगाल 9.74,

चना,13.76, गुजरात 15.68, अरहर 9.88 झारखंड 11.38, मसूर 9.88 मध य प्रदेश 11.39, दलहन 10.79 गुजरात 12.75, राई सरसो 14.12, हरियाणा 22.17, तिलहन 10.54 तमिलनाडु 20.43 प्रति हेक्टेयर कुंतल। इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए यूपी एग्रीज ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के उन जिलों को चुना है, जिनका उत्पादन अपेक्षाकृत कम है। 4000 करोड़ के निवेश से छह साल में 30% उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य

सरकार और संस्था का उम्मीद है कि वह किसानों, वैज्ञानिकों के जरिए नवाचार और तकनीक के प्रयोग इनपर 4000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए उत्पादकता में 30 फीसद तक वृद्धि कर सकते हैं। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की उत्पादकता पहले से अधिक है। ऐसे में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों की बढ़ी उत्पादकता यूपी को दुनियां का फूड बास्केट बनने के राह पर अग्रसर करेगी। क्योंकि इसके बावजूद भी संभावना अभी बाकी रहेगी।

संक्षिप्त खबरें

मणिपुर में शांति के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाएं मोदी – गहलोत

राजस्थान, एजेंसी। मणिपुर सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और थौबल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (2) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। छात्र आंदोलन के बीच पूरे मणिपुर में पांच दिन के लिए इंटरनेट सेवा निलंबित की गयी। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह जानकारी दी है। इसके अलावा शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि मणिपुर में ड्रोन, 'हाईटेक' मिसाइल हमले के बाद अत्याधुनिक रॉकेट के अवेशष मिले। कांग्रेस मणिपुर को लेकर काफी ज्यादा सरकार की अलोचना कर रही हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर मणिपुर में हो रही हिंसा पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूर्वोत्तरी राज्य में शांति स्थापित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने की मंगलवार को अपील की।

राहुल गांधी की मानसिकता विदेशी, बाहर जाने पर करते है देश का अपमान – दिनेश शर्मा

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस व भाजपा की आलोचना की। इस पर भाजपा हमलावर हो गई है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की विदेशी मानसिकता खत्म नहीं हुई है। वह जब भी बाहर जाते हैं, तो भारत को गाली देते हैं। उनको अटल जी ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए, जो विपक्ष में रहते हुए भी विदेश में देश की तारीफ करते थे। अमेरिका में जाकर यह कहना कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है, गलत है। शर्मा ने कहा भारत आज तेजस जैसे विमान बना रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने कई कीर्तिमान गढ़े हैं।

राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगी अर्पणा यादव

लखनऊ, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगी। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। अपर्णा यादव को पिछले सप्ताह राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक कार्यभार नहीं संभाला है। ऐसी अटकलें थीं कि वह उपाध्यक्ष पद पर अपनी नियुक्ति से नाराज थीं। यह भी अटकलें थीं कि वह सपा में शामिल हो सकती हैं।हालांकि, अपर्णा के करीबी सूत्रों ने मंगलवार को पुष्टि की कि वह बुधवार सुबह औपचारिक रूप से आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगी। अपर्णा ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लग गया। जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पिछले सप्ताह बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था

और अपर्णा यादव और चारू चौधरी को एक वर्ष की अवधि या राज्य सरकार के अगले निर्णय तक उपाध्यक्ष बनाया गया था। अपर्णा यादव सपा संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। वह अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं। अपर्णा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ा था।

चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से बर्खास्त करना चाहती है भाजपा - मंत्री आतिशी

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा विधायकों की ओर से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र पर सियासी घमासान जारी है। मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से बर्खास्त करना चाहती है। आतिशी ने कहा कि भाजपा का एकमात्र काम चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को गिराना है। भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं खरीद पाई, इसलिए अब वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र कर रही है। अगर भाजपा षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराती है, तो आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीरो सीटें आएंगी। भाजपा का एक ही काम है, चुनी हुई सरकार को गिराना। भाजपा जहां चुनाव नहीं जीतती, वहां विधायकों के खरीद–फरोख्त की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने का प्रयास करती है। दिल्ली में भी भाजपा ने यही काम किया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। वह आम आदमी पार्टी के विधायकों नहीं खरीद सकी, इसलिए अब चोर दरवाजे से सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही है। आतिशी ने कहा, मैं भाजपा को यह बता दूं कि, दिल्ली के लोग ये सारा षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए यदि कोई एक आदमी काम करता है।

चुनाव निष्पक्ष होते तो नहीं होते ये नतीजे, बीजेपी को नहीं मिलती इतनी सीटें – राहुल

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में मेरा प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तीन दिवसीय अमेरिका दौरा जारी है। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में स्थित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा की चुनाव से पहले इस बात पर चर्चा होती थी कि संस्थाओं पर कब्जा किया गया है। आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली, मीडिया, जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है।

हमारे बैंक खातों को बंद किया

राहुल गांधी ने कहा कि गरीब भारत और उत्पीड़ित भारत ये समझ चुका है कि संविधान के खत्म होने पर देश खत्म हो जाएगा। गरीब इसे गहराई से समझ चुके है। गरीब जानता है की ये लड़ाई संविधान की रक्षा करने वालों और इसे नष्ट करने वालों के बीच छिड़ी हुई है। आज के समय में जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़ा है। सब कुछ साथ में आया। अगर चुनाव निष्पक्ष होते को बीजेपी 246 सीटों के करीब होती। उनके पास आर्थिक लाभ भी था जबकि वो हमारे खाते सील कर चुके थे।

निर्वाचन आयोग पर साधा निशाना

निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी इच्छाओं को ही चुनाव आयोग ने पूरा किया। चुनाव अभियान ऐसा था कि मोदी देशभर में अपना प्रचार कर सके। ये पूर्ण तरीके से एक नियंत्रित चुनाव था।

झारखंड में विधायकों–सांसदों को खरीदने और पार्टी तोड़ने के लिए घूम रहे हैं केंद्रीय मंत्री – हेमंत सोरेन

झारखंड, एजेंसी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दल–बदलकर भाजपा में शामिल हुए चंपई सोरेन के क्षेत्र में पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंत्री घूम रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों–सांसदों को खरीदने और तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व सीएम

विधायकों और सांसदों को खरीदने और पार्टी को तोड़ने के लिए केंद्रीय और अपने मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे चंपई सोरेन के प्रभाव वाले कोल्हान प्रमंडल के चांडिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता हमारे राज्य में विधायकों–सांसदों को खरीदने के लिए घूम रहे हैं। ये पैसे के बल पर पार्टी को तोड़ते हैं। कभी बोलते हैं कि इतने विधायक हमारे साथ हैं तो कभी कहते हैं इतने सांसद हमारे साथ हैं। सोरेन ने कहा कि जनता इनको नहीं चुनती है, ये लोग पैसे से सरकार बनाते हैं। राज्य की जनता को ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि पैसा छापने की मशीन इन लोगों ने घर में रख ली है और सोचते हैं कि इसकी बदौलत पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा, "हमने जब 2019 में सरकार बनाई, उसके दूसरे दिन से ही इसे गिराने की साजिश रची जाने लगी।

अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करना नहीं चाहती भाजपा - प्रियंका

नई दिल्ली, एजेंसी। शिक्षक भर्ती प्रकरण पर अब 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब तलब किया है। अब सभी को कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार है, लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा, "यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भाजपा ने जैसा युवा और सामाजिक न्याय विरोधी रवैया अपनाया है, वह हैरान करने वाला है। दोहरा खेल, खेलकर आरक्षित और अनारक्षित– दोनों श्रेणी के युवाओं पर सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से आघात किया जा रहा है। पहले भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाला कर सैकड़ों दलित, पिछड़े अभ्यर्थियों का हक मारा और अब भी भाजपा की मंशा इस प्रकरण को लटकाने और भटकाने जैसी ही

है। यह अन्याय बंद होना चाहिए।" आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा, "69000 शिक्षक भर्ती (2018) में आरक्षण में हुए घोटाले पर 16 अगस्त 2024 को इलाहाबाद, उच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगाते हुए को न्याय से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए तीन महीने का समय दिया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कष्टदायी है। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का न्याय प्रदान करने का आग्रह करता हूं। क्योंकि इनके पांच वर्ष पहले ही सरकार और अधिकारियों की हठधर्मिता की भेंट चढ़ चुके हैं। हमारी पार्टी इस मामले पर नजर बनाए हुए है और छात्रों के अधिकार के लिए हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। इसकी परीक्षा 2019 में हुई थी। परीक्षा के बाद कटऑफ के आधार पर अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में 19 हजार सीटों पर घोटाला हुआ है। बीते दिनों इस संबंध में उन्होंने दावा किया था कि इस भर्ती में ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह महज 3.86 फीसद ही आरक्षण मिला।

जो लोग 400 पार का दावा करते थे, वे 240 पर सिमट गए - तेजस्वी

बिहार, एजेंसी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस आरोप का समर्थन किया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुए होते तो भाजपा 240 सीट तक भी नहीं पहुंच पाती। लोकसभा में विपक्ष के नेता फिलहाल अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां सोमवार को प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटीमें उन्होंने दावा किया कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो भाजपा 240 सीटों के आसपास भी नहीं आती। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री यादव से गांधी के इस आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "यह कोई रहस्य नहीं है कि भाजपा के विरोधियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर, जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा है, केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ गठबंधन करने से पिछले सभी पाप धुल जाते हैं। यादव का इशारा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की ओर था। अजित

पवार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसके कुछ दिनों बाद वह अपने चाचा शरद पवार की अगुवाई वाली राकांपा को तोड़ पश्चिमी राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में शामिल हो गए थे। यादव ने यह भी कहा, जो 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वे सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गए। यह तो बस शुरुआत है। मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में असंतोष और बढ़ रहा है। हालांकि, राजद नेता ने भरोसा जताया कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीत हासिल करेगा। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यादव ने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि राज्य के चुनावों में स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहमियत रखते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मतगणना के दिन गड़बड़ी न होती, तो महागठबंधन 2020 में ही सरकार बना लेता। हमें राजग से सिर्फ 12,000 वोट कम मिले। यादव ने अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए चलाए जा रहे कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। वह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे बेटे हैं और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं।

हम जल्द ही लिथियम–आयन बैटरी निर्यात करने की स्थिति में होंगे' – केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

नई दिल्ली, एजेंसी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत जल्द ही लिथियम–आयन बैटरी निर्यात करने की स्थिति में होगा, रिचार्जेबल बैटरी जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए आवश्यक हैं। ईवी वृद्धि के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 64वें सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने अनुमान लगाया कि 2030 तक म्ट बाजार में 1 करोड़ की बिक्री होगी। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि 2030 तक EV फाइनेंस बाजार 5 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि वे पेट्रोल और डीजल के "खिलाफ" नहीं हैं, लेकिन उनका मानना घ्है कि लोगों को प्रदूषण से सुरक्षा की जरूरत है। गडकरी स्वच्छ ईंधन पर जोर देने और वाहन

निर्माताओं से EV और हाइड्रोजन पर ध्यान देने का आग्रह करने के लिए जाने जाते हैं। कार्यक्रम में, गडकरी ने उद्योग से नई तकनीक अपनाने और पेट्रोल और डीजल के बारे में चिंता न करने का आग्रह किया। पिछले सप्ताह गडकरी ने कहा था कि बहुत जल्द देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए किसी और सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी।

संपादकीय

महिलाओं की आर्थिक समृद्धि

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वन विभाग को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के सभी संभव प्रयास करने कहा है। वन उत्पादों से जुड़े कार्यों एवम अन्य आजीविका मूलक कार्यों में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं जिसके बेहद ही सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ वन विभाग संयुक्त वन प्रबंधन के तहत वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों को वन संरक्षण और प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल कर आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग प्रशस्त करता है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियां स्थानीय ग्रामीणों से मिलकर बनती हैं जो वन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं एवं वन संसाधनों के साझा उपयोग की अवधारणा से प्रेरित हैं। वन विभाग इन समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे वन पर निर्भर लोगो की आजीविका में सुधार हो सके। छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में बसे छोटे से गांव मड़ई की 11 महिलाओं का मां महामाया स्वसहायता समूह ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से अपनी आय के स्त्रोतों में वृद्धि कर जीवन स्तर को ऊँचा किया जा सकता है। वन विभाग के सहयोग से इस समूह ने एक साधारण कृषि–वनीकरण की पहल को एक फलते–फूलते आर्थिक उद्यम में बदल दिया है। वन विभाग के मार्गदर्शन से एवं अपनी उद्यमिता से इस समूह की महिलाओं ने अब तक सात लाख रूपये से ज्यादा की आय अर्जित कर ली है। उनकी यह यात्रा न केवल आर्थिक समृद्धि की है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। इस यात्रा की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2018–19 में माँ महामाया स्व–सहायता समूह की अध्यक्ष मीरा बाई और सचिव सुमित्रा तथा समिति की सदस्यों केवल्या, बुधकुंवर, रमेशिया, मनीषा, सेमकुंवर, मैकिन, लौंग कुंवर, सुखंता, और सुक्षेन ने साथ मिलकर, पथर्रा (रुमगा) राजस्व क्षेत्र की 5 हेक्टेयर भूमि में 2,000 आम के पेड़ लगाए। इन महिलाओं ने दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली, चौसा, बॉम्बे ग्रीन जैसी लोकप्रिय किस्मों के साथ–साथ स्थानीय किस्मों के भी आम के पेड़ लगाए। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया यह कदम केवल एक वृक्षारोपण अभियान नहीं था बल्कि हरित आवरण को बढ़ाने, मृदा नमी संरक्षण में सुधार करने, और स्थानीय समुदाय के लिए स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने की एक सुनियोजित रणनीति थी। समूह की दीदियों ने बताया कि शुरुआती वर्षों में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले वर्ष में आम के पौधों की देखभाल के लिए उन्हें जमीन की गहरी जुताई करनी पड़ी। जिससे पौधों की जड़ें मजबूत हों और मिट्टी में नमी बनी रहे। इस दौरान उन्होंने सब्जियों की खेती नहीं की, क्योंकि नए आम के पौधों के लिए और भी देखभाल की जरूरत थी। हालांकि कोई मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वर्ष 2019–20 में, जब आम के पेड़ थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने अंतरवर्ती स्थानों में सब्जियां उगानी शुरू कीं। बीन्स, टमाटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, मटर, मिर्च, भिंडी, प्याज, सूरन, अदरक, हल्दी, लौकी, करेला, और कद्दू जैसी सब्जियों की खेती से होने वाली आय का उपयोग उन्होंने समूह की जरूरतों को पूरा करने और अगले मौसम के लिए बीज और खाद खरीदने में किया। वर्ष 2020–21 और 2021–22 के वर्षों में समूह ने आम के पेड़ों की देखभाल के साथ–साथ सब्जियों की खेती का विस्तार किया। उन्होंने अपने बगीचे में विविध प्रकार की सब्जियां उगाईं और उनकी बिक्री से आय अर्जित की। इस दौरान उन्होंने आम के पौधों से फूल हटाने का कठिन निर्णय लिया ताकि पेड़ों की वृद्धि बेहतर तरीके से हो सके और भविष्य में अच्छी फसल मिल सके। वर्ष 2022–23 में समूह की मेहनत रंग लाई। आम के पेड़ पूर्ण रूप से विकसित हो गए और अच्छी फसल दी। उन्होंने 4,203 किलो आम को स्थानीय और बिलासपुर बाजारों में बेचा। जिससे उन्हें इस पहल की शुरुआत से अब तक 7 लाख रुपये से ज्यादा का मुनाफा हुआ। यह आर्थिक लाभ उनकी मेहनत, धैर्य और योजना का प्रत्यक्ष प्रमाण था। वर्त्तमान में भी मां महामाया स्वसहायता समूह ने 98 प्रतिशत जीवित पेड़ों की दर के साथ अपनी सफलता को बनाए रखा है। उनकी यह पहल न केवल स्थानीय रोजगार और आर्थिक लाभ को बढ़ावा दे रही है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत, इस समूह की पहल गुड प्रैक्टिस का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पहल ने यह सिद्ध किया है कि सही मार्गदर्शन और सामुदायिक सहयोग से कैसे ग्रामीण महिलाएं न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकती हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। अपने वर्तमान कृषिवानिकी की उद्यमिता की सफलता से प्रेरित होकर यह स्व–सहायता की दीदियां सब्जियों और आमों के परिवहन के लिए ई–रिक्शा खरीदने पर विचार कर रही हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में वे आम के स्वाद में विशेषीकृत एक लघु आइसक्रीम निर्माण की इकाई स्थापित करने की योजना बना रही हैं, जिससे उनकी आय में और वृद्धि हो सके।

अमेरिका में शीर्ष पद पर कोई महिला नहीं रही

आदित्य

भारतीय उपमहाद्वीप के देश इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने बाकी दुनिया से बहुत पहले ही महिला नेताओं को उच्च पदों पर बिठाया है। दुनिया की पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री 1960 में श्रीलंका (जो तब सीलोन था) की सिरीमावो भंडारनायके थीं। भारत की "लौह महिला" इंदिरा गांधी इसके तुरंत बाद 1966 में उभरीं। इस क्षेत्र में अन्य पथप्रदर्शक मुस्लिम देश में पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री थीं, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो 1988 में, और उसके बाद बांग्लादेश की बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना वाजेद क्रमशः 1991 और 1996 में प्रधानमंत्री बनीं। म्यांमार की आंग सान सू की जनता की वास्तविक नेता रही हैं, हालांकि 1990 में उनकी जीत को अस्वीकार कर दिया गया था और उनकी पार्टी ने 2015 में सत्ता संभाली थी। यहां तक घ्कि नेपाल में भी 2015 में बिद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति बनी थीं। हालांकि, लोकतंत्र और सभी तरह के प्रगतिशील आंदोलनों के वैश्विक चौंपियन, संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष पद पर कोई महिला नहीं रही है। जबकि महिलाएं उपराष्ट्रपति (कमला देवी हैरिस), विदेश मंत्री (कोंडोलीजा राइस, मैडलीन अलब्राइट और हिलेरी क्लिंटन), प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष (नैन्सी पेलोसी) और यहां तक घ्कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार (हिलेरी क्लिंटन ने 2016 में डोनाल्ड

ट्रम्प की तुलना में लगभग तीन मिलियन अधिक लोकप्रिय वोट जीते, लेकिन फिर भी चुनावी कॉलेज में हार गईं) के पदों पर पहुंच गई हैं – वे च्ज्ै के रूप में ओवल ऑफिस के लिए अंतिम कट नहीं बना पाईं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर के उन 113 देशों में से एक है, जहां शीर्ष पद पर कोई महिला नहीं रही है। लिंग भेदभाव और लैंगिक भेदभाव के बारे में अक्सर प्रचलित सिद्धांतों में से एक यह है कि मजबूत सैन्य संस्कृति और परमाणु क्षमता वाले देश स्वाभाविक रूप से महिलाओं को शीर्ष पर रखने के खिलाफ हैं। यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि रूस और चीन के लिए भी सही है, जो "महाशक्ति" का दर्जा पाने के अन्य दावेदार हैं। इस दोषपूर्ण तर्क में निहित है कि कठिन परिस्थितियों में महिलाएँ "पर्याप्त रूप से मजबूत" नहीं होंगी, जिससे युद्ध की घोषणा हो सकती है। लेकिन इस सिद्धांत को इजराइल की गोल्डा मेयर (योम किप्पुर युद्ध 1973), भारत की इंदिरा गांधी (बांग्लादेश युद्ध 1971) या यहाँ तक कि ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर (फॉकलैंड युद्ध 1982) के उदाहरणों से नकार दिया जाता है। एंजेला मर्केल, जैसिंडा आर्डेन, त्साई इंग–वेन आदि जैसे कई अन्य लोगों ने खुद को संभाला और अपने देशों को इस्पात, निर्णायकता और सहानुभूति के दुर्लभ संयोजन के साथ आगे बढ़ाया। महिलाओं के इनकार के पीछे कोई विश्वसनीय कारण नहीं बताया गया है, सिवाय निर्विवाद भेदभाव के। इसी पृष्ठभूमि में हिलेरी रोडम क्लिंटन ने पिछले महीने शिकागो में हाल ही में हुए डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में "सबसे ऊंची, सबसे कठोर कांच की छत" को तोड़ने की उम्मीद को फिर से जगाया। डोनाल्ड ट्रम्प की अति–मर्दाना अपील को हराने के लिए कमला हैरिस पर दांव लगाते हुए, हिलेरी ने अमेरिकी महिलाओं की सामूहिक यात्रा को याद कियारू "साथ मिलकर, हमने सबसे ऊंची, सबसे कठोर कांच की छत में बहुत सी दरारें डाल दी हैं"। और फिर वह बड़े महत्व पर चली गईंरू "जब हममें से किसी एक के लिए कोई बाधा गिरती है, तो यह हम सभी के लिए रास्ता साफ करती है"। फिर उन्होंने अमेरिकी सपने के एक अब तक गायब टुकड़े का संकेत देते हुए सुझाव दियारू "उस कांच की छत के दूसरी तरफ कमला हैरिस अपना हाथ उठाकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ले रही हैं"। हालांकि, यह एक ऐसा कोण है जिसे कमला ने खुद आक्रामक तरीके से पेश नहीं किया हैरू शायद उन्हें स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है और वे अंतिम चरण में रणनीति के साथ वही बात कह सकती हैं, ताकि तटस्थ लोगों का दिल जीत सकें। अभी, वे ष्अभियोक्ता बनाम अपराधीष् थीम के साथ जीत पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो इस तथ्य को दोहराता है कि श्री ट्रम्प को कई न्यायालयों में औपचारिक रूप से दोषी ठहराया गया है और 34 गुंडागर्दी के लिए दोषी ठहराया गया है। ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है, क्योंकि वे सांख्यिकीय रूप से आगे हैं। इससे पहले, ष्चुनावी योग्यताष् सुविधाजनक पुरुष वरीयता के लिए एक कोड वाक्यांश था। लेकिन एक स्पष्ट रूप से अस्थिर राष्ट्रपति जो बिडेन की छाया में उपराष्ट्रपति के रूप में एक आश्वस्त रिकॉर्ड के साथ, कमला शीर्ष पद के लिए अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकती हैं। उन्होंने पहले ही इस तरह के बयानों के साथ डोनाल्ड ट्रम्प को परेशान करना शुरू कर दिया है उन भूमिकाओं में मैंने सभी प्रकार के अपराधियों का सामना किया– महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले शिकारी, उपभोक्ताओं को ठगने वाले धोखेबाज, अपने लाभ के लिए नियम तोड़ने वाले धोखेबाज। इसलिए, मेरी बात सुनिए जब मैं कहता हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रकार को जानता हूंष्। इसने मि. ट्रंप के पास प्रतिशोध में बढ़त हासिल करने और अधिक हानिकारक ष्आत्म–लक्ष्योंष् के लिए और भी अधिक जगह बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। मि. ट्रंप ष्सत्ता के दुरुपयोगष् शब्द का साकार रूप हैं, और इतिहास शिक्षाप्रद है कि उन्हें जितनी अधिक शक्ति दी गई है, उतने ही अधिक लोगों (विशेषकर महिलाओं) को उन्होंने चोट पहुंचाई है। महिलाओं के प्रति उनका जाना–पहचाना व्यवहार और टिप्पणियां उनके सत्ता के दुरुपयोग की मूल झलक रही हैं। एक घायल और ध्रुवीकृत दुनिया में, कमला हैरिस कई सामाजिक पूर्वाग्रहों – जाति, जातीयता, आव्रजन, धर्म, रंग और लिंग – का व्यक्तिगत अनुभव लेकर आती हैं, क्योंकि उन्होंने इसे सहन किया है। वह लिंग के लिए पुष्टि कर सकती हैं, जैसे राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जाति के लिए किया था ऐसा इसलिए क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से अधिक योग्य, सक्षम है और अमेरिका को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम है। एक आदर्श दुनिया में लिंग को बातचीत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और श्री ट्रम्प को हराकर वह ऐसी अपेक्षाओं की ष्सामान्यताष् को स्थापित करेगी। लिंग पर अधिक जोर न देकर, कमला आत्मविश्वास से अपनी राय, नीतियों और अनुभवों को पेश कर रही है – यह अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए, हालांकि दुख की बात है कि कुछ लोगों की प्रतिगामी मान्यताओं को देखते हुए ऐसा नहीं है। इसलिए, उस कांच की छत को तोड़ने का महत्व है। आखिरकार, राष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस का प्रदर्शन कैसा होगा, इसका लिंग से कोई लेना–देना नहीं है।

सरकार के अपराजिता विधेयक के बारे में खतरे की घंटी

विनोद

हाल ही में कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र जांच के लायक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पत्र ममता बनर्जी की सरकार द्वारा पारित अपराजिता महिला और बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में कई कानूनी लाल झंडे उठाता है। बलात्कार के लिए कठोर दंड निर्धारित करते हुए, विधेयक ने एक विशेष मामले में – बलात्कार और चोट के कारण पीड़ित की मृत्यु या पीड़ित के वानस्पतिक अवस्था में चले जाने के मामले में – एकमात्र दंड के रूप में मृत्यु की सिफारिश की है। कानून के जानकार इस बात से सहमत हैं कि यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के एक फैसले में बताया था कि मृत्युदंड को किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता हैय यहां तक कि जस्टिस वर्मा समिति, जिसे यौन हिंसा से संबंधित कानूनों और आपराधिक न्याय प्रथाओं की जांच करने के लिए गठित किया गया था, ने भी मृत्युदंड को निवारक के रूप में इस्तेमाल करने का विरोध किया था। दुनिया भर के आंकड़े इस ठोस कानूनी स्थिति की पुष्टि करते हैं। इस विधेयक को लेकर अन्य चिंताएँ भी हैं। विशेष कार्य बल तथा समर्पित जांच न्यायालयों की स्थापना की दिशा में प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि इन एजेंसियों तथा संस्थाओं को धन, बुनियादी ढांचा तथा कार्मिक नहीं दिए जाते जो उन्हें प्रभावी बना सकें। क्या ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे? विधेयक में यौन अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख नहीं हैरू भारतीय न्याय संहिता भी इस विषय पर निराशाजनक चुप्पी बनाए रखती है। आलोचकों ने कहा है कि विधेयक का प्रारूपण कहीं अधिक प्रतिनिधिक हो सकता थारू नागरिक समाज के सदस्यों सहित विविध हितधारकों के साथ परामर्श करने की पारंपरिक प्रथा का पालन नहीं किया गया। इन सीमाओं को एक साथ लिया जाए तो यह पुष्टि होती है कि विधेयक का प्रारूपण सत्ताधारियों की ओर से एक झटके में लिया गया कदम था, जब उन्हें संकट से निपटने के लिए गंभीर सार्वजनिक दबाव का सामना करना पड़ा। न्याय में देरी अवांछनीय हैय इसी तरह, न्याय देने में अत्यधिक जल्दबाजी अक्सर समस्याग्रस्त – लोकलुभावन – पदों को अपनाने की ओर ले जा सकती है जो रोग के बजाय लक्षणों का इलाज करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा अंतर्निहित संरचनात्मक विकृतियों का परिणाम है। इन बाधाओं का सामना करने के लिए निरंतर, गहन प्रयासों की आवश्यकता है – सुविचारित निवारक उपाय, पुलिस व्यवस्था में सुधार, दोषसिद्धि दरों में सुधार, अंतरंग स्थानों और लोगों को संवेदनशील बनाना आवश्यक उपायों में से हैं। जब तक कानून सुधारात्मक उपायों की तुलना में दंडात्मक उपायों को प्राथमिकता देते रहेंगे, तब तक सार्थक परिवर्तन मायावी बने रहेंगे।

आत्महत्या पर कहानी बदलना

ललित

आत्महत्या एक कठिन और संवेदनशील विषय है, जो अक्सर चुप्पी और कलंक में लिपटा रहता है। पीढ़ियों से, आत्महत्या से जुड़ी चर्चाओं में गलतफहमी, निर्णय और भय की झलक मिलती रही है। हालाँकि, आत्महत्या की रोकथाम में सार्थक प्रगति करने के लिए, कथा को बदलना जरूरी है – शर्म से भरी बातचीत से हटकर ऐसी बातचीत की ओर बढ़ना जो समझ, करुणा और समर्थन को बढ़ावा दे। विश्व स्तर पर आत्महत्या से प्रभावित लोगों की महत्वपूर्ण संख्या के बावजूद, यह कई संस्कृतियों और समाजों में एक वर्जित विषय बना हुआ है। यह चुप्पी मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के बारे में खुली चर्चा को रोकती है, जो संघर्ष कर रहे लोगों को मदद लेने से हतोत्साहित करती है। आत्महत्या से जुड़ा कलंक इस तरह की गलत धारणाओं को जन्म देता है कई लोग अभी भी मानते हैं कि आत्महत्या एक स्वार्थी कार्य है या व्यक्तिगत कमजोरी का परिणाम है। यह गलत धारणा उन जटिल और भारी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और परिस्थितिजन्य कारकों को नजरअंदाज करती है जो किसी को अपनी जान लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में, अवसाद और चिंता सहित मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करना एक कमजोरी या टालने योग्य विषय माना जाता है। परिणामस्वरूप, आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे व्यक्ति अक्सर न्याय या गलत समझे जाने के डर से अपने संघर्षों को छिपाते हैं। कुछ लोग आत्महत्या को नैतिक या नैतिक विफलता के रूप में देखते हैं, जो अक्सर धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी होती है। यह दृष्टिकोण केवल आत्महत्या के विचार से जूझ रहे लोगों के बोझ को बढ़ाता है, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि वे अपने नैतिक दायित्वों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों कहानी बदलना महत्वपूर्ण है आत्महत्या के इर्द–गिर्द कहानी बदलना एक ऐसा माहौल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ लोग न्याय के डर के बिना अपने मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में बात करने में सुरक्षित महसूस करें। अधिक दयालु, समझदार दृष्टिकोण मदद कर सकता हैरू जब आत्महत्या को कलंकित नहीं किया जाता है और व्यक्तिगत विफलता के बजाय एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में माना जाता है, तो अधिक लोग मदद मांगने और अपनी जरूरत की देखभाल प्राप्त करने में सहज महसूस करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और आत्महत्या के जोखिम की शुरुआती पहचान जान बचा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत पेशेवर सहायता प्राप्त करने में देरी को कम करती है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलेपन और सहानुभूति की संस्कृति व्यक्तियों को सहायता के लिए अपने समुदायों पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। परिवार, दोस्त और सहकर्मी आत्महत्या की रोकथाम में मूल्यवान सहयोगी बन सकते हैं। एक नया दृष्टिकोण आत्महत्या पर कहानी को प्रभावी ढंग से बदलने के लिए, कलंक और गलत सूचना के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

यहाँ बताया गया है कि हम कैसे शुरुआत कर सकते हैंरू मानसिक स्वास्थ्य पर शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। जिस तरह लोग टूटी हुई हड्डी के लिए चिकित्सा सहायता लेते हैं, उसी तरह उन्हें अवसाद या चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए देखभाल लेने के लिए भी समान रूप से प्रोत्साहित महसूस करना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा अभियान मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कलंक को कम करने में मदद कर सकते हैं, यह उजागर करके कि मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष आम हैं और मदद मांगना ताकत का संकेत है, कमजोरी का नहीं। आत्महत्या किसी एक कारक या घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य कारकों का एक जटिल परस्पर क्रिया है। इनमें मानसिक स्वास्थ्य विकार, आघात, वित्तीय कठिनाई, रिश्ते की कठिनाइयाँ, मादक द्रव्यों का सेवन और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं। इस जटिलता को स्वीकार करने से व्यक्ति को दोष देने से ध्यान हटाने में मदद मिलती है, उन व्यापक परिस्थितियों को समझने में जो आत्महत्या के विचारों में योगदान दे सकती हैं। आत्महत्या के विचारों से जूझने वाले और बच गए व्यक्तियों की कहानियाँ साझा करना उन अन्य लोगों को आशा प्रदान कर सकता है जो पीड़ित हैं। दूसरों ने अपने सबसे बुरे पलों से कैसे निपटा और कैसे उनसे उबरा, यह सुनकर संभावना और तन्यकता की भावना पैदा हो सकती है। ये कहानियाँ इस मुद्दे को मानवीय बनाती हैं और आत्महत्या के बारे में चुप्पी तोड़ती हैं। आत्महत्या के चेतावनी संकेतों के बारे में आम जनता और पेशेवरों को शिक्षा प्रदान करना, साथ ही मदद कैसे की जाए, यह भी महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा या गेटकीपर प्रशिक्षण जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम लोगों को जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करना, सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया देना और उन्हें उचित संसाधनों की ओर मार्गदर्शन करना सिखाते हैं। यह ज्ञान मदद पाने में आने वाली बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है। समुदाय और संस्थान सुरक्षित, गैर–निर्णयात्मक स्थान बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं जहाँ व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या पर चर्चा करने में सहज महसूस करते हैं।

एक्ट ईस्ट पालिसी पर पुनर्विचार की आवश्यकता

संजय

एक्ट ईस्ट पॉलिसी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से नई दिल्ली की सबसे स्थायी और सुसंगत विदेश नीति रणनीतियों में से एक रही है। शुरू में लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में शुरू की गई, यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित थी। समय के साथ, यह दृष्टिकोण एक व्यापक रणनीति में विकसित हुआ है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों के साथ गहन जुड़ाव और सीमा पार आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देकर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों को संबोधित करना शामिल है। हालाँकि, पड़ोसी बांग्लादेश और म्यांमार में हाल की राजनीतिक अस्थिरता ने नीति की प्रभावशीलता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं, जो दर्शाता है कि अब एक महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। पड़ोस में अचानक बदलावरू अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार को हटाने के साथ बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया। उनका प्रशासन, जिसे लंबे समय से भारत के लिए एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी के रूप में देखा जाता था, व्यापक विरोध के बीच गिर गया। भारत के लिए, जिसने हसीना की सरकार के साथ एक मजबूत संबंध विकसित किया था, यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण झटका है। इस बदलाव ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है और भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर संदेह पैदा कर दिया है। इस राजनीतिक उथल–पुथल के तत्काल नतीजों में ट्रेन सेवाओं का निलंबन और भारत–बांग्लादेश सीमा पर माल और लोगों की आवाजाही को रोकना शामिल है। भारत के लिए एक और अधिक चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश में नया नेतृत्व चीन या यहां तक घ्कि विडंबना यह है कि पाकिस्तान की ओर अपना झुकाव बदल सकता है, जिसके उत्पीड़न के कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के जटिल और अक्सर प्रतिकूल संबंध हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, बांग्लादेश और भारत के बीच पहले से मौजूद घनिष्ठ सहयोग को बनाए रखने के लिए कम इच्छुक हो सकती है। इस तरह के बदलाव के परिणामस्वरूप भू–राजनीतिक पुनर्संरेखण हो सकता है जो भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को संभालना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। यूनुस प्रशासन ने द्विपक्षीय संबंधों के संभावित पुनर्मूल्यांकन का संकेत दिया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि भारत के साथ पहले हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की समीक्षा की जा सकती है या उन्हें बांग्लादेश के प्रतिकूल पाए जाने पर रद्द भी किया जा सकता है। यह, भारतीय –वित्तपोषित परियोजनाओं की बढ़ती जांच और तीस्ता जल–साझाकरण संधि जैसे विवादास्पद मुद्दों पर नए सिरे से चर्चा के साथ, इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने में भारत के सामने आने वाली जटिलताओं को उजागर करता है। म्यांमार में जुड़ाव की दुविधारू भारत के लिए म्यांमार का रणनीतिक और आर्थिक महत्व काफी है, खासकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी) के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के प्रभाव को आगे बढ़ाने और आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए। हालांकि, फरवरी 2021 में सेना के कब्जे से उपजी म्यांमार में राजनीतिक उथल–पुथल एक गंभीर चुनौती है। 8 फरवरी, 2024 को, भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और पूर्वोत्तर राज्यों में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के बाद म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) को समाप्त करने का फैसला किया। भारत–म्यांमार– थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, जो भारत के उत्तर–पूर्व में मणिपुर को म्यांमार में मांडले और बागान के माध्यम से थाईलैंड के माई सोत से जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण परियोजना है। जबकि राजमार्ग का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, म्यांमार में चल रहे संघर्ष के कारण शेष 30 प्रतिशत पर प्रगति रुकी हुई है। इसी तरह, नई दिल्ली को हनोई से जोड़ने के इरादे से बनाई गई महत्वाकांक्षी ट्रांस–एशियन रेलवे लिंक ने भी बहुत कम ठोस प्रगति की है। इसके अलावा, पूर्वी भारतीय बंदरगाह कोलकाता को म्यांमार के रखाइन राज्य के सित्वे से समुद्र के रास्ते जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए कलादान मल्टी–मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का भविष्य भी खतरे में है। हाल ही में अराकान सेना द्वारा पलेत्वा पर कब्जे ने स्थिति को और जटिल कर दिया है यह महत्वपूर्ण स्थान इस क्षेत्र को दक्षिण–पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाता है, जो इसे भारत के एईपी के केंद्र में रखता है। हालाँकि, मणिपुर में चल रहे जातीय तनाव, जिसे अक्सर दक्षिण–पूर्व एशिया के लिए भारत का ष्प्रवेश द्वारष् कहा जाता है, एईपी के तहत भारत की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पटरी से उतारने की धमकी देता है। इन संघर्षों का पूर्वोत्तर क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जो ऐतिहासिक रूप से जातीय संघर्ष और उग्रवाद से ग्रस्त रहा है। पड़ोसी देशों से फैल रही अस्थिरता, म्यांमार से शरणार्थियों की आमद और बांग्लादेश से इसी तरह के आंदोलनों की संभावना ने मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में तनाव को बढ़ा दिया है। भारत सरकार द्वारा मणिपुर में धार्मिक स्वतंत्रता को निलंबित करने का निर्णय भारत–म्यांमार सीमा पर लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने वाली मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) को समाप्त करना न केवल सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करता है, बल्कि सीमावर्ती समुदायों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी बाधित करता है। एईपी के तहत भारत के ष्साझा भाग्यष् के दृष्टिकोण को सफल बनाने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिरता आवश्यक है। एईपी का भविष्य बुनियादी ढांचे में सुधार से परे हैय यह क्षेत्र के भीतर और पड़ोसी देशों के साथ शांति और विश्वास को बढ़ावा देने पर टिका है। एक नई वास्तविकता को नेविगेट करनारू इन चुनौतियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति को व्यापक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

होली चाइल्ड स्कूल में यातायात जागरुकता व सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मॉदड़, पुलिस अधीक्षक डॉ0 अजय पाल शर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात देवेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक यातायात जी0डी0 शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मिथीलेश मिश्रा के द्वारा होली चाइल्ड स्कूल में यातायात जागरुकता व सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम "पहले हेलमेट बाद में चाभी" स्लोगन के साथ वहाँ पर मौजूद 550 बच्चो को जागरुक किया गया।

जिलाधिकारी ने उपस्थित बच्चों से कहा कि अपनें परिवार में सभी सदस्यो को भी हेलमेट की की विशेषता के बारे में जागरुक करें तथा साथ ही साथ शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाते हुए मदिरापान करके वाहन न चलाने, ओवर स्पिड मे वाहन चलाने, ब्लैक फिल्म के प्रयोग, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता, हेलमेट, सीट बेल्ट, सड़क पर अवैध रुप से खड़े वाहनो के पार्किंग, के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया एवं चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के उलंघन करने वाले 208 के विरुद्ध संपूर्ण चालान करके 2,15,000 का राजस्व वसूली की गयी।

हरदोई की प्राची यादव ने लहराया परचम, कृषि प्रसार में गोल्ड मेडल हासिल किया

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) जिले की प्राची यादव ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के सप्तम दीक्षांत समारोह में अपनी शानदार सफलता का परचम लहराया है। कृषि प्रसार विभाग, कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज, प्रयागराज की छात्रा प्राची ने अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। यह सम्मान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के हाथों प्राप्त हुआ। प्राची की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे हरदोई जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता–पिता और शिक्षकों को दिया, जिनके सहयोग और प्रेरणा से वह इस मुकाम तक पहुंची हैं। प्राची की इस कामयाबी पर हरदोई के लोगों ने गर्व जताया है, और उसे जिले की बेटियों के लिए प्रेरणा बताया।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। नेवढ़िया के कादीपुर में रुपये के लेन देन को लेकर हुई हत्या के दोषी अनिल गौड़ को अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने बुधवार को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को देने का आदेश दिया।अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

अभियोजन के अनुसार दो दिसम्बर 2017 की सुबह वादी के रिश्तेदार श्रवण पटेल ने मोबाइल से सूचना दिया कि उसके भाई महेंद्र पटेल का शव कादीपुर दरगाह के पास नहर में मिला है।वहा पहुंचा तो काफी भीड़ लगी थी। भाई के शव को पहचाना कहा कि उसका भाई एक दिन पहले सुबह भाड़ा ढोने के लिए गया था। आशंका है कि भाड़े के लेन देन के विवाद को लेकर किसी ने उसकी हत्या कर दी है। दो दिसंबर को नेवढ़िया थाने में एफआईआर दर्ज हुआ।

विवेचना में नेवढ़िया के कसियांव निवासी अनिल गौड़ का नाम सामने आया। चार दिसम्बर को पुलिस द्वारा अनिल के घर की तलाशी लेने पर मृतक की शर्ट ,लोवर, कैचीं, व लोहे की रॉड बरामद हुआ। अनिल ने महेंद्र पटेल की निर्ममता से लोहे के रॉड से सिर पर मारकर हत्या किया था। 15 फरवरी 2018 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया।सात दिसम्बर 2018 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में धारा 302 आईपीसी में आरोप तय किया गया। सरकारी वकील सतीश रघुवंशी व वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने 11 गवाहों को पेश किया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अनिल को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

नशे के विरुद्ध विषय पर जागरूकता गोष्ठी आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी रविन्द कुमार मॉदड़ के निर्देशानुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय के कुशल प्रवेक्षण में महिला कल्याण विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा पंचायत इण्टर कालेज मोकलपुर, मड़ियाहूँ में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम 2015 यथासंसोधित 2021, यौन हिसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं एक युद्व नशे के विरूद्व विषय पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में किया गया।

कार्यक्रम बाल सरंक्षण अधिकारी चन्दन राय द्वारा किशोर न्याय (बालकों का देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम 2015 यथासंशोधित 2021, यौन हिसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की चर्चा करते हुए स्पान्सरशिप योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि कन्या सुमंगला योजना अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई धनराशि प्राप्त हो रही है। प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म पर 5000 रू0, द्वितीय श्रेणी बालिका के एक वर्ष के टीकाकरण पूरा होने पर 2000, तृतीय श्रेणी बालिका के कक्षा 01 में नामंकन होने पर 3000, चतुर्थ श्रेणी बालिका के कक्षा 06 में नामांकन होने पर 3000, पंचम श्रेणी में बालिका कक्षा–09 में 5000, षष्ठम श्रेणी में बालिका का स्नान्तक या समकक्ष में नामांकन कराने पर 7000 रू0 मिलने है इसका आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न हेल्प लाइन नं0 (1098, 181, 1090, 112, 102, 108,) के बारे मे बच्चो को जानकारी दी गयी एवं उनको प्रश्नो का भी जवाब दिया गया।

पुलिस अधीक्षक, अजय पाल शर्मा के निदेशानुसार साइबर आफिसर साइबर थाना जौनपुर संग्राम सिह यादव बच्चो के बीच उपस्थित हुए और बच्चों को साइबर काइम के बारे में बताया कि किसी भी गैजेट को इण्टरनेट से कनेक्ट कर कुसित विचारो से किसी को क्षति पहुचाई जाती है, वह साइबर अपराध होगा। साइबर अपराध वर्तमान में दो तरह से प्रचलित है। धन के धोखाधड़ी का अपराध एवं सोशल साइट के अपराध। धन के अपराध के बचने के लिए आवश्यक है कि आप किसी भी अन्जान लिंक को क्लिक न करें। किसी अन्जान व्यक्ति द्वारा भेजे गये स्केनर को स्केन नही करें। किसी भी स्थिति में मे अपने मोबाइल पर आयी हुई ओ0टी0पी0 नही बतायें। हमेसा अपने मोबाइल के ऐप को 02 स्टैप वेरिफिकेशन में रेखे। सब कुछ करने के बाद भी आप ओ0टी0पी0 नही बताते है तो आपका आर्थिक नुकसान नही होगा। ओ0टी0पी0 एक प्रकार से आपका डिजीटल सिग्नेचर है। सोशल साइट के अपराध में दूसरे की आई0डी0 बनाकर पैसे की मॉग कराना या डीप फोटो या विडियो बनाना बहुत ही गम्भीर विषय हो गया है। उन्होंने कहा कि सोशल साइट की सैटिंग में जाकर प्राइबेसी सुनिश्चित करे। हमेश 02 स्टैज वेरिफिकेशन रखें, जिससे आप सुरक्षित रखें, किसी अपरचित की विडियो काल आती हो तो उसे न उठायें अगर रिसीब करते है तो कैमरे को बन्द रखें। साइबर अपराध होने पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप टोल फ्री नं0 1930 पर शिकायत दर्ज कराये या अपने नजदीक थाने के साबर सेल पर जायें जितना जल्दी आप शिकायकत करेगे उतनी ही आपके धन के वापसी की सम्भावना ज्यादा होगी।

अंकित पांडे का उत्तराखंड पीसीएस में हुआ चयन, परिजनों शुभ चिंतको में खुशी की लहर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सिराजे हिंद की सरजमी जौनपुर हमेशा से आईएएस– पीसीएस अधिकारियों का केंद्र बिंदु रहा है।जिले के माधोपट्टी गांव इसका उदाहरण है जो पूरे विश्व पटल पर अंकित है।इस गांव में सबसे ज्यादा आईएएस–पीसीएस अधिकारी हुए हैं। इस कड़ी को एक बार फिर आगे बढ़ते हुए जनपद के होनहार छात्र ने उत्तराखण्ड पीसीएस में चयनित होकर परिवार सहित पूरे जनपद का मान बढ़ा दिया।अंकित पांडेय का चयन जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर उत्तराखंड में हुआ है। अंकित पाण्डेय नगर के बसन्त कुंज कालोनी पॉलिटोनिक चौराहा निवासी डा. यूके पाण्डेय एवं गीता पाण्डेय के पुत्र हैं जिनका उत्तराखण्ड पीसीएस में जिला आपूर्ति अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। अंकित ने बताया की इनकी आरंभिक शिक्षा हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल तथा टीडी कालेज जौनपुर से हुआ है। जिसके बाद उच्च शिक्षा दिल्ली से पूरी हुई। इनके बड़े भाई एम्स दिल्ली में सर्जन हैं। मूलतरू ये लोग प्रतापगढ़ जिले के कुण्डा के निवासी हैं जो पिछले कई वर्षों से जौनपुर में रहते हैं। फिलहाल अंकित के चयन ने जौनपुर एवं प्रतापगढ़ जिला गौरवान्वित हुआ है। अंकित ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर की कृपा, माता–पिता की तपस्या, बड़े भाई और दीदी का सहयोग तथा गुरुजनों का मार्गदर्शन बताया। अमित ने कहा कि कोई क्षेत्र में जाकर आम जनता के लिए अपने गरीबों की सेवा करना चाहते हैं मेरे विभाग द्वारा जो भी संभव होगा मदद करने का प्रयास करुंगा।

अंकित पांडेय ने दो बार यूपीएससी की परीक्षा दी है जिसमे वह इंटरव्यू तक पहुंचे है। लेकिन वह कुछ अंको से पीछे रह गए।किस्मत ने उनका साथ नही दिया जिससे उनका चयन नही हो पाया।

नही रहें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री ओम दादा

मृत्युंजय प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रवक्ता डॉ मनीष वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये सूचना दी।कि आज प्रातः सात बजे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं उत्तर प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष श्री सुनील कुमार शर्मा ष्ओम दादाष्का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया।उनका अंतिम संस्कार वी आई पी पुराने जेल रोड वाले शमशान घाट में उनके पुत्र ने मुखाग्नि दे कर किया। पार्थिव शरीर के अन्तिम दर्शन कर उत्तर प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री कृपा शंकर मिश्र, प्रवक्ता डॉ मनीष वर्मा,शहर अध्यक्ष लखनऊ श्री एम डी मुस्तफा, पूर्व पार्षद दल के महासचिव श्री रविशंकर मिश्र, पूर्व विधायक श्री श्याम किशोर शुक्ल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री वीरेन्द्र मदान वीरेन्द्र मदान,श्री राम प्रभाकर मिश्र,आर टी आई विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन श्री पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, श्री महेन्द्र कुमार आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित

की व दादा के पुत्र व परिजनों को ढांढस बंधाया।

जिला चिकित्सालय में वाहन स्टैंड न होने के चलते गायब हो रहे हैं बाइक

अयोध्या। जिला पुरुष चिकित्सालय में वाहन स्टैंड न होने के चलते आये दिन किसी न किसी मरीजों व उनके तीमारदारों की बाइक गायब होती रहती है। इनके अलावा यहां पर आने वाले कर्मचारियों के बाइक को भी यहां पर सक्रिय वाहन चोर देखते ही देखते गायब कर दे रहे हैं।इन वाहन चोरो पर न तो यहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों का कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है।इसका जीता–जागता उदाहरण बुधवार को दिखाई दिया।जब बाइक चोर ने जिला चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड शैलेन्द्र सिंह निवासी बभनियावां थाना रौनाही की बाइक यूपी 42 ए एच 8599 वाहन चोर ने चुरा ले गया।जो बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक मे उक्त चोर साफ साफ दिखाई दे रहा है।इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दे दिया है।फिलहाल इस तरह की घटनाएं वहां पर बाइक चोरी की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहां के कर्मियों ने बताया कि

यहां पर वैध रुप से वाहन स्टैंड का संचालन काफी वर्षों से नहीं हो रहा है।बीच में अवैध रुप से वाहन स्टैंड का संचालन कुछ ठेकेदारों द्वारा हो रहा था।परंतु इधर काफी महीनों से यहां पर अवैध रुप से संचालित वाहन स्टैंड बंद हो चुका है।जिसके चलते यहां पर इलाज कराने आने वाले मरीज अपने अपने वाहनों को इधर उधर खड़ी कर देते हैं। वहां पर स्टैंड न होने के चलते आये दिन वाहन चोर बाइकों को गायब करते हैं। यहां पर तैनात एक कर्मी ने बताया कि पिछले एक सालों से अब तक यहां से लगभग 200 से अधिक अधिक बाइक चोरो ने गायब कर दिया है। जिसमें कई बाइकों को पुलिस ने बरामद कर इसमें शामिल बाइक चोरो को गिरफ्तार कर बाइक को उनके स्वामियों के सुपुर्द किया है। बताते चलें कि यहां के लोगों ने बताया कि जब तक यहां चाहे अवैध रुप से ही वाहन स्टैंड संचालित था तब तक लोगों की बाइक सुरक्षित थी।परन्तु जिला चिकित्सालय में अब वाहन स्टैंड न होने के चलते वाहन चोरी में बढ़ोतरी हुई है। इस गंभीर समस्या पर न तो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ उत्तम कुमार,नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस विभाग का ध्यान जा रहा है।जिसका खामियाजा यहां पर आने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है।जिससे वाहन स्टैंड न होने के चलते आये दिन वाहन चोर कई बाइकों को चुरा रहे हैं।इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ उत्तम कुमार ने बताया कि दो ढाई वर्ष से यहां पर कोई वाहन स्टैंड संचालित नहीं है। सभी वाहनों को यहां पर तैनात सुरक्षा कतार में खड़ी करवाते हैं।वही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पाण्डेय ने बताया कि स्टैंड आदि का ठेका नगर निगम के दायरे में आता है।

दीक्षांत समारोह में पर्यावरण सरंक्षण को मिलेगा बढ़ावा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय में आगामी 22 सितंबर को अपना 28 वां दीक्षा समारोह आयोजित करने जा रहा है। इस बार पर्यावरण सरंक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गयी है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार कुछ नए और सकारात्मक बदलाव किए गए है। समारोह की शुरुआत इस बार जल भरने और सरस्वती वंदना के स्थान पर पर्यावरण सरंक्षण से संबंधित काव्य पाठ से की जाएगी।।इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों और उपस्थित जनसमूह में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है।

इस बार बड़े बुके (गुलदस्ते) के लेन देन पर रोक लगाई गई है। और उसकी जगह अब फूलों की पंखुड़ी भेंट की जाएगी। इसके अलावा मोमेंटो की जगह पुस्तक दी जाएगी। ताकि विद्यार्थीयों को उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकें। दीक्षा समारोह में विशेष रूप से कक्षा पांच से आठ तक के 30 बच्चों की फलों की टोकरी और ड्राइंग की किताबें उपहार स्वरूप भेंट की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली और रचनात्मक को बढ़ावा देना है। समारोह में भाग लेने वाले गोल्ड मेडलिस्ट और उपाधिकारक विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है। कि वे भारतीय परिधान में आये।

समारोह के दौरान 10 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी किट वितरित किया जाएगा । इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा गोंद लिए गए। पांच गांवों के आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए विशेष प्रतियोगताओ का आयोजन किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गांव के बच्चों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सम्मानित करेगी।

जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें अधिकारी व कर्मी - ऋतु सिंह

अयोध्या। राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति एवं वाहनों की फिटनेस, मानक के अनुसार पंजीयन,दर्पण पोर्टल सेवाये, आईजीआरएस आदि पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण आरटीओ विभाग के अधिकारी व कर्मी त्वरित निस्तारण करें।यह निर्देश समीक्षा बैठक में आरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान कही। इस मौके पर सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी व अम्बेडकरनगर के एआरटीओ प्रशासनध्प्रवर्तन व संभागीय निरीक्षक अयोध्या मौजूद रहे। उन्होंने समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सितम्बर माह में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करते हुये राजस्व की शत– प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें व बकाया वसूली हेतु सबसे बड़े बकायेदारों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुये संभाग के सभी बकाये दारों से दूरभाष व डोर टू डोर नांकिंग की गति तेज करते हुये प्रभावी बकाया कर वसूली करें।आरटीओ प्रशासन ने अधिकारियों व कर्मियों को निर्देश दिया कि दलालों अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध जीरो टालरेन्स की नीति अपनाई जाएगी।राजस्व लक्ष्य के अनुरूप शत–प्रतिशत प्राप्ति ना किये जाने पर आरटीओ द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिये कि गत वितीय वर्ष के सापेक्ष कम से कम 20 प्रतिशत मासिक एवं क्रमिक वृद्धि हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी वाहन स्वामी अपना कर घर बैठे parivahan.gov.in पर जा कर आन लाइन माध्यम से कर जमा कर सकते हैं। बैठक में एआरटीओ प्रशासन डॉ आर पी सिंह,एआरटीओ सुल्तानपुर नन्दकुमार, एआरटीओ अम्बेडकरनगर सत्येन्द्र यादव, एआरटीओ अमेठी सर्वेश कुमार सिंह,आरआई प्रेम सिंह एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

रुड़की ब्लॉक में सिलाई प्रशिक्षण कैंप का उद्घाटन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

रुड़की, हरिद्वार रुड़की ब्लॉक के चार गांव रहीमपुर, किशनपुर, राठौर देव तथा पनियाला गांव को जिला युवा केंद्र हरिद्वार द्वारा चयनित कर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना आज इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के अवसर पर ब्लाक खंड अधिकारी रुड़की रोड सुमन कुड़िया ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर जिला युवा केंद्र हरिद्वार के अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा की। इस अवसर पर युवा केंद्र क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी मुकेश भट्ट, अनिल कोहली ने मुख्य अतिथि का स्वागत करके किया। मुख्य अतिथि ब्लाक खंड अधिकारी रुड़की सुमन कुड़िया ने कहा इस प्रयास से ग्रामीण इलाकों में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा महिलाओं को रोजगार मिलने में आसानी रहेगी। महिलाएं सिलाई केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने रोजगार का साधन स्वत प्राप्त कर समाज में महिला सशक्तिकरण द्वारा मजबूती स्थिति में होगी। उद्घाटन समारोह के दौरान समीर मुदस्सिम अली, राहुल बाबू रुड़की ब्लॉक कमांडर सत्य राज, भगवानपुर ब्लॉक कमांडर केशव, पूजा, रॉकी तिवारी तथा सचिन ने उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान किया।

अपराधियों से भी ज्यादा जौनपुर के दोहरा ने में मचा रखा है आतंक, मानवाधिकार संगठन ने दोहरा बंद करने का उठाया बीड़ा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । शिक्षा मूली, इमरती और इत्र के लिए मशहूर जौनपुर में एक और चीज मशहूर हो रही है दोहरा...इस दोहरे का सेवन करने के बाद बहुत से लोग माउथ कैंसर का शिकार हो रहे है। स्वास्थ्य के लिए दोहरा कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीएचयू और टाटा कैंसर अस्पताल मुंबई ने भी इसे कैंसर की वजह बताया है। जौनपुर से हर साल माउथ कैंसर के 15–20 मरीज टाटा कैंसर अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे में दूसरे कैंसर संस्थानों में कितने मरीज जौनपुर से आते होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी की जौनपुर शहर में पिछले कई सालों से सुपारी सुरती और कई प्रकार के सामानों को मिलकर दोहरा के नाम से बेचा जा रहा है आए दिन वाराणसी कैंसर हॉस्पिटल में जो मरीज पहुंचते हैं उसमें से 70: मैरिज जौनपुर के ही होते हैं कई बार शासन प्रशासन को बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा बताए जाने के बाद और शासन प्रशासन के कई बार प्रयास करने के बाद भी यह दोहरा का जाल जौनपुर से खत्म नहीं हो रहा है। छोटी–छोटी दुकानों पर गलियों में नुक्कड़ों पर यहां तक की जौनपुर के कई नामी चौराहों पर दोहरा बेचा जा रहा है। 8 बाई 10 की दुकान में बैठकर दोहरा बेचने वाला एक व्यापारी लाखों करोड़ों की संपत्ति बना ले रहा है लेकिन उसी दोहरा की चपेट में आने वाला नवयुवक अपने घर के लाखों रुपए अपने इलाज में ही बर्बाद करवा देता है। सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिल रही है की कई परिवार ऐसे हैं जिनकी तीनों पीढ़ियां अर्थात दादा पोता और पिता सब दोहरा खाते हैं यहां तक की अब महिलाओं ने भी इस व्यसन का आनंद लेना शुरू कर दिया है भले ही खाद्य विभाग व पुलिस प्रशासन ने कई बार इसको रोकने का अभियान चलाया लेकिन वह सफल नहीं रहे उल्टा जितनी बार उन्होंने अभियान चलाया उतनी बार और नए दोहरा बनाकर बेचने वाले लोग सामने आ गएआने वाली नई पीढ़ी इसका शिकार ना हो जाए इसलिए शासन प्रशासन को इसकी सुध लेते हुए तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करके अभियान चलाकर इस नशे को जौनपुर से पूर्णतया समाप्त करना चाहिए। जनपद में बढ़ रही दोहरे की लत से नौजवानों को बचाने के लिए अब मानवाधिकार संगठन ने भी बीड़ा उठाया है। मानवाधिकार आयोग लखनऊ के अध्यक्ष रुपेश चौधरी ने जनपद में दोहरा बंद करने के लिए दोहरे के खिलाफ जंग छेड़ दी है।उन्होंने बताया की पुलिस अधीक्षक डॉ अजय पाल शर्मा व जिला अधिकारी से मुलाकात किया । इस पर पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित करके कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। दोहरे जैसी गंभीर बीमारी की बारे में पत्रकारों से बात करते हुए जनपद के वरिष्ठ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बृजेश कुमार कनौजिया ने बताया कि आज दोहरे के कारण काफी लोग माउथ कैंसर का शिकार हो रहे हैं। ज्यादातर मामलों में जो मेरे रिसर्च पेपर कहते हैं जो लोग गुटका दोहरा सुरती जैसी चीजों का सेवन करने से लगभग 33. 3 प्रतिशत लोग माउथ कैंसर का शिकार हो रहे हैं।

नूर मंजिल मनोरोग चिकित्सा केंद्र ने मनाया विश्व आत्महत्या रोकथाम जागरूकता दिवस

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। नूर मंजिल मनोरोग चिकित्सा केंद्र, लखनऊ ने विश्व आत्महत्या रोकथाम जागरूकता दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटर्न्स द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य आत्महत्या के खतरों, विचारों, संकेतों की पहचान और समय पर हस्तक्षेप के महत्व पर मनो–साक्षरता को बढ़ाना था। नाटक में एक समृद्ध परिवार की कहानी को दर्शाया गया, जो बेरोजगारी, अलगाव, पढ़ाई में असफलता, हानि और जीवन की कठिनाइयों के कारण बिखर जाता है। इस नाटक ने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने के खतरों को उजागर किया और समय पर पेशेवर मदद की अहमियत को दर्शाया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ नैदानिक मनोवैज्ञानिक और रिश्तों के पुनर्निर्माण विशेषज्ञ डॉ. अंजलि गुप्ता के मार्गदर्शन में, अस्पताल प्रशासन की सहमति से किया गया। इस अवसर पर मनोचिकित्सक डॉ. राजपूत ने कहा कि आत्महत्या के प्रमुख कारणों में से एक अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा न कर पाने की अपराधबोध की भावना है। उन्होंने लोगों से एक–दूसरे की मदद करने, बातचीत शुरू करने और जरूरत पड़ने पर सहायता माँगने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि ष्जीवन अनमोल है और आपकी एक बातचीत किसी की जान बचा सकती है। नूर मंजिल मनोरोग चिकित्सा केंद्र के प्रशासन ने पेशेवर सहायता प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हुए, अपनी पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का समापन मैथिलीशरण गुप्त की कविता की पंक्तियों के साथ हुआ 'नर हो न निराश करो मन को, जो जीवन में आशा और दृढ़ता बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं।

महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर

अयोध्या, संवाददाता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व मणिराम दास की छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें रविवार शाम 6:30 बजे यूरीनरी समस्या और मुंह के रास्ते कम आहार लेने की समस्या के चलते आईसीयू में डॉ. दिलीप दुबे की निगरानी में भर्ती किया गया था। सोमवार दोपहर जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, महंत जी की हालत गंभीर बनी हुई है और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम निरंतर उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रख रही है। रुँ ।ज्ब्- उत्तर प्रदेशरू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को लखनऊ के मेदांता अस्पताल के प्ब्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रही है। पिछले कुछ दिनों से महंत जी का ग्वालियर में उपचार चल रहा था, स्थिति में सुधार नहीं होने के चलते उन्हें मेदांता अस्पताल में लाया गया। मेदांता लखनऊ की मेडिकल विशेषज्ञों की टीम उनके बेहतर इलाज के लिए निरंतर प्रयासरत है। इससे पहले भी महंत दास मेदांता अस्पताल में गंभीर स्थिति में चिकित्सकों का उपचार लेते रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास भी कल शाम लखनऊ पहुंच गए हैं। वह इस समय मेदांता में महंत दास के साथ मौजूद हैं। उन्होंने अमर उजाला को खास बातचीत में बताया था कि महंत दास की तबीयत फिलहाल ठीक है। लेकिन फिर भी उनको चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री महंत का हाल–चाल लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वैसे इसके पहले जब भी ट्रस्ट अध्यक्ष यहां भर्ती हुए हैं।

डिंपल यादव ने भाजपा को घेरा, बोलीं- सच बर्दाशत नहीं कर पाती बीजेपी

आगरा, संवाददाता। इन दिनों में यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी है। विभिन्न पार्टियों के नेता जीत के लिए कमान संभाले हुए दिख रहे हैं। मैनपुरी जिले की करहल सीट पर भी उपचुनाव होना है। यह सीट इसलिए काफी चर्चा में है, क्योंकि यहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से सांसद बनने के बाद, उन्होंने यह सीट छोड़ी है। मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी और सपा नेता डिंपल यादव, वर्तमान सांसद हैं। डिंपल मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। यहां करहल में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। डिंपल यादव ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सच बोल रहे हैं।

जब भी सच बोला जाता है, तो भाजपा को तकलीफ पहुंचती है। उन्होंने बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। कहा कि मैं युवाओं से यह बात पूछना चाहती हूं, कि क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? सपा सांसद ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? पूरी दुनिया जानती है कि आज उत्तर प्रदेश और देश में बेरोजगारी है। कहा कि सच बोलने में कोई जगह नहीं देखी जाती है। सच, सच होता है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, ष्सच बोला जा रहा है। जब भी सच बोला जाता है तो भाजपा को इससे तकलीफ पहुंचती है। मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से पूछना चाहती हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है?

संक्षिप्त खबरें

बाइक की टक्कर से वृद्धा की मौत

बांदा। घर से खेत जा रही वृद्धा को सामने से आई बाइक ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अछाह गांव निवासी कौशलपति (65) रविवार को दोपहर अपने घर से खेत जा रही थी। तभी अछाह व कोरम गांव के बीच नहर पटरी के सामने बाइक सवार ने सामने से टक्कर मार दी। वृद्धा को पहले बबेरू सीएचसी, फिर बांदा जिला अस्पताल उसके बाद प्रयागराज ले गए थे। वहां से डॉक्टरों ने उसे कानपुर के लिए रेफर किया था। कानपुर ले जाने के लिए वह वापस गांव आ रहे थे, तभी उसने दम तोड़ दिया। देवर कृष्ण कुमार ने बताया कि पति की 20 साल पहले लकवा से मौत हो चुकी है। पांच बीघा जमीन में खेती किसानी से गुजर बसर होता है। एक पुत्र एक पुत्री है। बबेरू कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि बाइक एक्सीडेंट में वृद्धा की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

ईएमओ ने मरीज के परिजनों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

बांदा, संवाददाता। जिला अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर में मरीज के तीमारदारों के साथ अभद्रता व मारपीट करने के मामले में अब ईएमओ डॉ. प्रदीप गुप्ता ने न्यायालय के आदेश पर दो महिलाओं समेत चार लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीजेएम न्यायालय में दायर किए गए वाद में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में तैनात ईएमओ डॉ. प्रदीप गुप्ता ने बताया कि वह 15 जून को सायंकालीन ड्यूटी पर थे। तभी बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अहार गांव निवासी कमलिया (50) को बबेरू सीएचसी से रेफर होने पर उसके परिजन ट्रामा सेंटर लाए थे। उसने फंदा लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया था। महिला को देखकर इलाज के निर्देश दिए थे। तभी महिला के देवर ने उनका कॉलर पकड़कर धमकाया था। तभी वह दो महिलाओं के साथ आ गया और अभद्रता करते हुए मारपीट की थी। जिस पर वार्ड ब्याय रिषभ व फार्मासिस्ट विजय सिंह ने बचाया। न्यायालय के आदेश पर दो महिलाओं समेत चार लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उधर, शहर कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। इससे पूर्व मरीज के परिजनों की तहरीर पर डॉक्टर, फार्मासिस्ट व वार्ड ब्याय के खिलाफ पूर्व में भी रिपोर्ट दर्ज है। उसकी विवेचना की जा रही है।

प्रधानाध्यापक भूले चाबी, नहीं खुला स्कूल का ताला

बाराबंकी, संवाददाता। विकासखंड निंदूरा क्षेत्र के नरपतिपुर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के खुलने का समय सुबह आठ बजे निर्धारित है। इसके बावजूद जिम्मेदारों की लापरवाही से स्कूल का संचालन शुरू करने में आए दिन देरी होती है। सोमवार को विद्यालय के गेट पर सुबह 11 बजे तक ताला लटकता रहा। इस कारण विद्यालय में पंजीकृत करीब 106 बच्चों को करीब ढाई घंटे तक स्कूल के बाहर खड़े रहना पड़ा। इसकी जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान विनोद कुमार मौर्य ने बच्चों को पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय के अंदर बैठाया और उनके लिए एमडीएम का प्रबंध कराया। इंचार्ज प्रधानाध्यापक संजय त्रिपाठी ने बताया कि विद्यालय में तैनात दोनों शिक्षिकाएं अवकाश पर थीं। वह विद्यालय आए थे लेकिन स्कूल गेट की चाबी घर पर ही भूल आए थे। इस लिए वापस घर जाकर चाबी लाने में देर हो जाने के कारण विद्यालय का ताला देरी से खुला। इस विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के साथ ही दो महिला शिक्षकों की भी तैनाती है। निर्धारित समय पर स्कूल का गेट न खुलने से पढ़ने के लिए पहुंचे बच्चे स्कूल के बाहर ताला खुलने के इंतजार में घूमते भटकते रहे। बीईओ सुषमा सेंगर ने बताया कि बताया कि स्कूल का ताला देर से खुलने की शिकायत मिली है। इस मामले की जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई तय की जाएगी।

अयोध्या में खनन माफिया बेखौफ, कर रहे थे अवैध मिट्टी खनन

अयोध्या, संवाददाता। अयोध्या जिले में खनन माफिया बेखौफ हो गए हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रुदौली क्षेत्र में शुजागंज पुलिस चौकी के पीछे रात के अंधेरे में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की तो खनन माफिया के गुर्गे फरार हो गए। इस दौरान यहां से आठ ट्रैक्टर ट्राली सीज की गई। इसी तरह पूराकलंदर थाना से चार किलोमीटर दूर मिट्टी खनन किया जा रहा था। खनन विभाग की टीम ने यहां पर भी छापेमारी कर तीन ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया है। खनन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मौके पर पुलिस टीम को भी बुला लिया गया था। पकड़े गए प्रत्येक ट्रैक्टर पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है।

स्कूल संचालक ने मासूम से की छेड़खानी

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के बरौली रोड स्थित एक शिक्षण संस्थान के संचालक पर कक्षा पांच में पढ़ने वाली छात्रा के पिता ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है। छात्रा के पिता ने बताया कि स्कूल संचालक कुलदीप द्वारा उसकी पुत्री से हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की गई। स्कूल जाकर विरोध करने पर उनके साथ विवाद भी किया गया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामले में इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच–पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

फाल्ट सही करते समय आपूर्ति शुरू होने से ट्रांसफार्मर से चिपका बिजली कर्मी, मौत

हरदोई, संवाददाता। पाली थाने के पास रखे ट्रांसफार्मर में आए फॉल्ट को सही कराने के दौरान अचानक आपूर्ति चालू हो जाने से प्राइवेट बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अवर अभियंता को मौके पर बुलाने पर अड़ गए। बिजली विभाग ने मृतक को विभागीय कर्मचारी मानने से इन्कार किया है। पाली के मोहल्ला बिरहाना निवासी मंजेश कश्यप (32) बिजली उपकेंद्र पर तैनात लाइन मैन के साथ प्राइवेट तौर पर रहकर बिजली मरम्मत का काम करता था। मंगलवार शाम पांच बजे थाने के पास सरस्वती स्कूल जाने वाली सड़क पर रखे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट गया। उसे सही करने के लिए मंजेश गया था। इसी दौरान आपूर्ति चालू हो गई और करंट लगने से मंजेश ट्रांसफार्मर में ही चिपक गया। आसपास के दुकानदारों ने इसकी जानकारी उपकेंद्र को दी तो आपूर्ति बंद की गई। मौके पर पहुंची पुलिस मंजेश को लेकर पीएचसी पहुंची।

यहां डॉक्टर आनंद शुक्ला ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में पत्नी चमेली, एक पुत्र और एक पुत्री है। प्रभारी निरीक्षक रमेशचंद्र पांडेय ने बताया कि तहरीर लेकर कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग के अवर अभियंता सुखपाल सिंह ने बताया कि मंजेश नाम का कोई कर्मचारी नहीं है। फॉल्ट सही करने के लिए ड्यूटी पर मौजूद लाइन मैन शटडाउन लेता है, लेकिन किसी ने भी शटडाउन नहीं लिया था।

तमंचा लगा ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 3.35 लाख लूटे

उन्नाव, संवाददाता। सफीपुर–चौधरीखेड़ा मार्ग पर मुंडा गांव के पास एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से बाइक सवार नकाबपोश तीन बदमाश 3.35 लाख रुपये लूट ले गए। पीड़ित के अनुसार, उसने विरोध किया तो नकाबपोश लुटेरों ने कनपटी पर तमंचा लगा दिया। आईजी–एसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित से जानकारी ली। आईजी ने घटना के जल्द खुलासे का निर्देश दिया है। आसीवन थानाक्षेत्र के गांव टिकराकुमेदान निवासी छेदनू प्रसाद कुरसठ कस्बे में जनसेवा केंद्र चलाता है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक का भी काम करता है। सोमवार को वह बैंक खाते से रुपये निकालने सफीपुर ब्रांच गया था। अलग–अलग दो खातों से उसने 3.35 लाख रुपये निकाले और 5:15 बजे बाइक से घर के लिए निकला। छेदनू प्रसाद के मुताबिक, सफीपुर–चौधरीखेड़ा मार्ग पर फतेहपुर चौरासी थाना के मुंडा गांव के पास शारदा नहर पर पहले से बाइक की लाइट बंद करके लुटेरे खड़े थे। उन्हें आता देख लुटेरों ने उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगा दी। हेलमेट लगाए एक लुटेरा अपनी बाइक को स्टार्ट किए खड़ा रहा और दो अन्य लुटेरों ने कनपटी पर तमंचा लगाकर बैग की बेल्ट को कटर से काट दिया। विरोध किया तो मारपीट की और बैग लूटकर भाग गए। घटना के तीन घंटे बाद रात 8:15 बजे छेदनू ने राहगीरों की मदद से बांगरमऊ–लखनऊ मार्ग पर मौजूद पुलिस कर्मियों को घटना की जानकारी दी। लूट की सूचना पर आसीवन, फतेहपुर चौरासी और सफीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित को साथ लेकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना, सीओ माया राय ने भी जांच की। लुटेरों की तलाश में रात भर पुलिस छानबीन करती रही लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मंगलवार सुबह आईजी प्रशांत कुमार ने एसपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित से घटना की जानकारी ली। उन्होंने दो किलोमीटर दूर डकौली गांव के बाहर शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। बैंक शाखा के भी कैमरों की फुटेज जांची गई है।

सीओ माया राय ने बताया कि फतेहपुर चौरासी थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। घटना की जांच की जा रही है। जल्द खुलासा किया जाएगा। ग्राहक जनसेवा केंद्र संचालक एक समय में रुपये नहीं निकलता था। वह कभी सुबह, कभी दोपहर तो कभी शाम को रुपये निकालता था। जिन रास्ते से संचालक जाता था, वह सुनसान है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि लुटेरों को इसका पता था। वहीं पुलिस घटना को अभी तक संदिग्ध मान रही है। पीड़ित के मुताबिक, वह बैग टांगे था लेकिन घटना से पहले शराब ठेके के कैमरे में जांच की गई तो उसमें पीठ पर बैग नजर नहीं आया है। आसीवन एसओ ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि घटनास्थल से पांच किलोमीटर दूर चौधरीखेड़ा पुलिया के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। फिर भी तीन घंटे बाद सूचना दी गई।

पहले भी हुईं लूट की घटनाएं

लगातार हो रहीं लूट और चोरी की घटनाओं से जनता परेशान हैं। 10 मई को आसीवन थानाक्षेत्र के पेसारी गांव निवासी जनसेवा केंद्र संचालक मोहम्मद फहीम के साथ लूट हुई थी। छह सितंबर को गहोली गांव निवासी सेवानिवृत्त फौजी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी विजय कुमारी के बैग से 60 हजार रुपए स्टेट बैंक में निकल गए थे। इसके साथ ही एक ही दिन में क्षेत्र में आठ चोरियों के साथ पहले हुईं चोरियों का अब तक खुलासा नहीं हुआ।

अनियमितता और लापरवाही पर दो चकबंदी अधिकारी समेत चार सस्पेंड

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेटलतीफी, लापरवाही और अनियमितता पर दो चकबंदी अधिकारियों समेत तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही कई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि महाराजगंज के ग्राम बैठवलिया में प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार करने में अनियमितता पर सहायक चकबंदी अधिकारी अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। बांदा के ग्राम सिलेहटा में अनियमितताओं पर चकबंदी अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। साथ ही तत्कालीन चकबंदीकर्ता कामता प्रसाद को निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चकबंदी आयुक्त ने बताया कि बिजनौर में चल रही चकबंदी में अनियमितता को लेकर विभिन्न गांव के किसानों ने शिकायत की थी। इस पर जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद निदेशालय स्तर पर समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच में चकबंदी के दौरान अनियमितता की शिकायत सही मिलने पर तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। विजय कुमार वर्तमान में मुजफ्फरनगर में बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के पद पर तैनात हैं।

लखनऊ नगर निगम से चकबंदी लेखपाल का संबद्धीकरण समाप्त

लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने अपने यहां संबद्ध मिर्जापुर के चकबंदी लेखपाल राजेंद्र कुमार यादव की अनियमितताओं की शिकायत की थी। इस पर संबद्धीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव

लखनऊ, संवाददाता। शासन के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय ने 17 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना संजय सिंघल के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की वजह से अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर को आईजी स्थापना बनाया गया है। इसके अलावा झांसी, सोनभद्र, उन्नाव, औरैया, महोबा, शाहजहांपुर, रायबरेली, संभल के पुलिस कप्तान बदले गए हैं।

डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना प्रभाकर चौधरी को अलीगढ़ रेंज का डीआईजी बनाया गया है। झांसी के एसएसपी राजेश एस. को शाहजहांपुर का एसपी बनाया गया है। वहीं गाजियाबाद स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी में तैनात सुधा सिंह को झांसी का एसएसपी बनाया गया है। सोनभद्र के एसपी डॉ. यशवीर सिंह को रायबरेली का एसपी बनाया गया है। उन्नाव के एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना को प्रयागराज पुलिस में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। शाहजहांपुर के एसपी अशोक को सोनभद्र का एसपी बनाया गया है। प्रयागराज कमिश्नरेट में पुलिस

कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। औरैया की एसपी चारू निगम को 47वीं वाहिनी पीएसी भेजा गया है। महोबा की एसपी अपर्णा गुप्ता को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट उपायुक्त दीपक को उन्नाव का एसपी बनाया गया है। संभल के एसपी कुलदीप सिंह गुनावत को प्रयागराज कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है।

कोविड के दौरान बंद की गयी भारत और नेपाल सीमा पर्यटकों के लिए खोली गयी

लखनऊ, संवाददाता। भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए खोल दी गयी है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोविड–19 के प्रकोप के दौरान बंद कर दी गयी थी। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सीमा के खुलने से पर्यटक भारत तथा नेपाल के प्राकृतिक व रमणीक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे, इससे दोनों देशों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल के बीच स्थित धनगढ़ी और गौरीफंटा क्रासिंग दो वर्षों से बंद थी। गौरीफंटा–धनगढ़ी सीमा को फिर से खोले जाने का प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष महत्व है। यह मार्ग विभिन्न परिदृश्यों तथा विविध वन्य जीवन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। उप्र के लखीमपुर में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित वन क्षेत्र है। घने जंगलों से घिरा यह इलाका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। हर साल बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमी यहां पहुंचते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के धनगढ़ी शहर से लगा हुआ है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि भारत की ओर से नेपाल जाने के इच्छुक पर्यटकों को बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान खासा आकर्षित करता है। नेपाल की सैर पर जाने वालों को बर्दिया उद्यान में बाघों और एक सींग वाले गैंडों की वृहद आबादी देखने को मिलती है। शुक्ला फांटा राष्ट्रीय पार्क लुभावने दृश्य और जैव विविधता का जीता–जागता उदाहरण है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा घास का मैदान है। वहीं, नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, पर्यटकों की पहली पसंद है। यह घने जंगलों, वन्यजीव सफारी और अद्भुत जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लंबे समय बाद भारत और नेपाल के पर्यटकों को एक–दूसरे देश में फिर से जाने और घूमने का अवसर मिलेगा। नेपाल में मौजूद पर्यटन स्थल न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है, बल्कि दोनों (भारत और नेपाल) देशों के बीच आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रवेश द्वार भी है। जयवीर सिंह ने बताया कि गौरीफंटा–धनगढ़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक बार फिर खुलना बौद्ध पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। यह मार्ग नेपाल से आने पर्यटकों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा सारनाथ, कुशीनगर जैसे पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करता है। वहीं, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आने वाले डेस्टिनेशन की रोमांचक यात्रा को प्रेरित करता है। इस द्विपक्षीय प्रवेश द्वार से निकट भविष्य में भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता के साथ प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत की गहरी समझ विकसित होने की उम्मीद है।

सरयू में समा गए चार आशियाने

सीतापुर, संवाददाता। बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी में कमी से सरयू नदी का जलस्तर नीचे खिसक गया है। सोमवार को सरयू का जलस्तर 117.35 मीटर दर्ज किया गया। रविवार की तुलना में पानी पांच सेमी कम हुआ है। लेकिन कटान थम नहीं रहा है। पिछले तीन दिनों में परमगोंडा के चार आशियाने कटकर सरयू में समा गए हैं। यहां बचे सिर्फ पांच घर भी कटान की कगार पर हैं। कटान नहीं थमा तो गांव का अस्तित्व खत्म हो सकता है। वहीं, तीन दिनों में लहरें 110 बीघा खेत फसलों समेत निगल गई हैं। उधर, बैराजों से सोमवार को तीन लाख चार हजार 390 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सरयू नदी का पानी दो दिन से 117.40 मीटर पर स्थिर था। सोमवार को जलस्तर में पांच सेमी कमी आई। पानी अब 117.35 मीटर पर पहुंच गया है। पानी काफी नीचे खिसकने से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। इसके बाद भी कटान तबाही मचा रहा है। परमगोंडा गांव लहरों के निशाने पर है। कटान के डर से यहां के लोग पहले ही अपना घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले चुके हैं। दो दिनों परमगोंडा के रामपाल, राजेश कुमार, जगतराम व ब्रजेश कुमार के घर कटकर सरयू नदी में समा चुके हैं।

15 घरों वाले परमगोंडा गांव में अब मात्र पांच घर बचे हैं। अब नदी की धारा रामविजय, नंदकिशोर, शिवकुमार, लालजी व रामअवतार के घरों की ओर बढ़ रही है। इन घरों की दूरी धारा से महज 50 मीटर से कम ही बची है। इधर तीन दिनों में रामपाल, राजेश व ब्रजेश की 15–15 बीघा, रामविजय व नंद किशोर की 30–30 बीघा, लालजी की पांच बीघा खेती फसल समेत कटान की भेंट चढ़ चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम व तहसीलदार व लेखपाल आए थे। उन्होंने शीघ्र आवासीय जमीन देने की बात कही है। लेकिन अभी तक पीड़ितों को जमीन व मुआवजा नहीं मिला है। राजेश ने बताया कि एक बार राहत सामग्री वितरित की गई थी।

गाजे-बाजे के साथ तहसील पहुंचे पूर्व मंत्री, सौंपा ज्ञापन

सीतापुर, संवाददाता। तहसील परिसर में सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा की अगुवाई में गाजे–बाजे संग सपा कार्यकर्ता पहुंचे। सभी ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसील प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा अपने आवास से कार्यकर्ताओं के साथ गाजे–बाजे के संग राम कुंड चौराहा, बजाजा चौराहा, चिक मंडी चौराहा होते हुए तहसील पहुंचे। जहां उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में राज्यपाल के नाम संबोधित 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन तहसीलदार अशोक कुमार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि चोरी, लूट, रंगदारी, अपहरण, सट्टा, जुआ स्मैक का जाल पूरे महमूदाबाद क्षेत्र में फैल चुका है। बीते एक माह में केसरवारा, आलमपुर, समदा, केलनपूर्वा, रसूलपनाह, हेलेपारा, कोदौरा, गोडैचा गांवों संग नगर क्षेत्र के मोहल्ला शिवाजी नगर, अमीरगंज, पुरानीबाजार, गुलरामऊ आदि जगहों पर चोरी व लूट की घटनाएं हुई हैं। इनमें से अधिकांश का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इस वजह से क्षेत्र में भय व्याप्त है। लोग रात को जाग कर पहरा दे रहे हैं। बताया कि बड़ी चोरी के मामले में जनपद में महमूदाबाद अव्वल है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।